PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA (HOUSING FOR ALL)

Municipal Corporation Shimla have conducted several meetings with the banks to take forward the Vertical 2-Credit Linked Subsidy of the Housing for All Mission in the Shimla City. In this regard various meetings have been conducted with the Banks. Many queries have been emerged and MC Shimla is trying to resolve all the issues with the help of UD, Shimla. Banks have asked to get NOC from the native village of the intended beneficiaries.

Under the vertical 1& 3, the task of land identification is going on. MC Shimla has identified land and the approval of the Hon'ble MC House will be obtained for the same. MC, Shimla is checking all the options to make the project financial viable on ground level.

The Urban Development department of Himachal Pradesh have hired one consulting firm, Stesalit Limited to implement the scheme in the 13 cities of Himachal Pradesh.

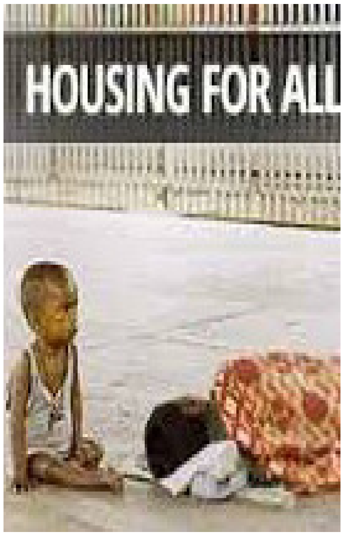

SMC- EU FUNDED PROJECT

26th April - 4th May, 2016:The international Exposure visit involving a team of 12 members from Municipal Corporation Shimla and CDD Society under the SMC-EU Project to Malaysia & Bangkok was successfully completed.

25th May, 2016 : The tenders were uploaded for setting up Fecal Sludge Treatment Plant (FSTP) & Community Toilet proposed at Bangala Colony, Totu and tenders were opened on 4th June & 31th May, 2016 respectively. After completion of codal formalities, the work will be awarded to qualifying Contractors.

1st June, 2016: Keeping in view the project visibility, EU Project sponsored caps and T-shirts depicting the logos of European Union & MC Shimla for the Supervisor's and Safai Karamchari Staff of MC Shimla deployed on special Duty during the President' visit to Shimla.

Housing for all
Ministry of Housing & Poverty Alleviation

First Anniversary of Atal Mission of Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)

स्पैशल हाऊस : एक साल पूरा होने पर नगर निगम ने बुलाया विशेष सदन, आयुक्त ने गिनाईं उपलब्धियां; बेहतर कार्य करने पर केंद्र से मिलेगी अतिरिक्त राशि

शिमला, 25 जून (वंदना): अमृत मिशन के तहत नगर निगम शिमला ने एक साल में 29 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों को अमलीजामा पहनाया है। इनमें से अधिकांश कार्य निगम द्वारा पूरे कर लिए गए हैं जबकि कुछेक कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। शनिवार को नगर निगम प्रशासन ने अमृत मिशन के एक साल पूरे होने के अवसर पर रोटरी टाऊन हॉल में विशेष सदन आयोजित किया। सदन की अध्यक्षता नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने की।

अमृत मिशन के तहत एक साल में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने के लिए मेयर संजय चौहान ने अधिकारियों समेत पार्षदों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और जनता के नुमाइंदों ने कम से कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि निगम को एक साल में मिले पैसों को खर्चने के लिए करीब 3 माह ही मिले थे, बावजूद इसके निगम ने बढ़िया काम करते हुए राशि लैप्स नहीं होने दी। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा भी खासतौर से मौजूद रहीं। उन्होंने एक साल के अंदर किए गए कार्यों के लिए निगम की सराहना करते हुए कहा कि सरकार निगम को हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है। इस दौरान सदन में डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर, पार्षद शशि शेखर, अनूप वैद्य, भारती सूद, कांता सुयाल, कला शर्मा, नरेन्द्र ठाकुर, संजय परमार, शैलेन्द्र चौहान, रजनी सिंह, सत्या कौंडल, मनोज कुठियाला व कल्याण चंद सहित अन्य पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे।

शिमला : बैठक को संबोधित करतीं अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा। (नरेश)

यहां होगा इतना पैसा खर्च

अमृत के तहत नगर निगम 3 सालों में शहर में वाटर सिस्टम को मजबूत करने के लिए 41.65 करोड़ रुपए खर्च करेगा जबकि पहले चरण में पानी पर 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे जबकि सीवरेज पर निगम 37.28 करोड़ 3 सालों में खर्च करेगा। पहले चरण में निगम 13.71 करोड़ खर्च करेगा। शहर के हर छोटे-बड़े नाले व नालियों का सही चैनेलाइजेशन कर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। निगम इसके लिए 3 सालों में 0.84 लाख खर्च करेगा जबकि पहले वर्ष में इस पर 0.28 लाख खर्च करेगा। इसके तहत शहर में पार्क निर्माण पर कुल 3 सालों में 2.16 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 0.72 लाख व्यय किए जाएंगे। वहीं शहर के अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर 6.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं।

अमृत के तहत निगम ने इन कामों पर खर्च किया पैसा

नगर निगम ने अमृत के तहत एक साल में शहर के पानी व सीवरेज पर अधिक पैसा खर्च किया है। इसमें से निगम ने तेजी से काम करते हुए जून, 2016 तक इस राशि से 14 अलग-अलग कार्य कार्यान्वित किए हैं। इन 14 में से अधिकांश कार्य अब पूरे हो गए हैं, जिसमें खोडन पंप हाऊस की मुरम्मत, पानी की लीकेज बंद करने पर 2.3 करोड़, 4.23 करोड़ रुपए के सीवरेज वर्कर्स सहित पानी की मेन लाइन की मुरम्मत मुख्य हैं। इसके अलावा अमृत के तहत 2.10 करोड़ से सब्जी मंडी में पार्किंग, 72 लाख से 8 हजार व 4 हजार क्षमता के वाटर टैंकर, 21 लाख से स्नो मशीन, कृष्णानगर में 9 लाख से नाला सुधार, टका बैंच में पार्क की इंप्रूवमैंट का काम प्रोग्रैस पर है। इस दौरान आयुक्त ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम चल रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए टाइम लाइन फिक्स करें, ताकि वे जल्द से जल्द पूरे हो सकें।

अमृत मिशन में असली काम तो अब शुरू होगा

राजधानी को 24 घंटे पानी दिलाएगा अमृत

मिशन का एक साल पूरा होने पर एमसी ने बैठक में योजनाओं का किया खुलासा

250 करोड़ रुपये मिशन के तहत राजधानी को अगले चार साल तक मिलेंगे

मकान हर घर को सीवरेज सुविधा से जोड़ा जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में होगा सुधार

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। अमृत प्रोजेक्ट के तहत राजधानी को 24 घंटे सातों दिन पानी मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी भी कर ली है। अमृत प्रोजेक्ट को शुरू हुए एक साल पूरा होने पर नगर निगम ने बैठक का आयोजन किया। इसमें शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा भी शामिल रहीं। बैठक की अध्यक्षता मेयर संजय चौहान ने की। उपमहापौर टिकेंद्र पंवर सहित पार्षद और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने कहा कि मिशन के तहत राजधानी शिमला को अगले चार सालों में कुल 250 करोड़ रुपये मिलेंगे। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए शिमला को 90 करोड़ और 2016-17 के लिए 70 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अमृत मिशन के तहत 24 घंटे सातों दिन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, हर घर को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना और एसटीपी अपग्रेड करना, नालों और नालियों की स्थिति में सुधार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सुधार जैसे क्षेत्रों में काम किया जाना है। योजना के तहत शिमला को 2020 तक केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी। बैठक में निगम पार्षद रजनी सिंह, शैलेंद्र चौहान, भारती सूद, नरेंद्र ठाकुर और कांता स्याल सहित अन्य पार्षद उपस्थित रहे।

पहले दस राज्यों में आने का लक्ष्य

आयुक्त पंकज राय ने बताया कि अमृत मिशन के तहत हिमाचल को पहले 10 राज्यों में स्थान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में मिशन के तहत बताए गए रिफार्म को गंभीरता से लेते हुए काम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से 28 रिफार्म बताए गए हैं जिनमें से शिमला ने 26 रिफार्म पूरे कर लिए हैं। रिफार्म पूरे होने की स्थिति में शिमला को 2.3 करोड़ की अतिरिक्त विकास राशि मिलेगी।

शिमला के रोटरी टाउन हाल में अमृत मिशन पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेते पार्षद और अमृत मिशन की योजनाओं का बखान करते आयुक्त पंकज राय।

अब तक हुए कार्य

- शहर में सीवरेज नेटवर्क विस्तार पर काम शुरू
- पानी की लाइनों में लीकेज दुरुस्त करने का काम शुरू
- स्नोडन पंप हाउस के पंप बदले गए
- पार्किंग निर्माण के लिए कर दिए गए हैं टेंडर
- पानी के छह वाटर टैंकर खरीदने की तैयारी
- बर्फ हटाने के लिए खरीदी जा रही है रोबट मशीन

14 प्रोजेक्टों को मिली मंजूरी

राज्य स्तर पर गठित स्टेट लेवल टैक्निकल कमेटी ने 29.58 करोड़ के 14 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इनमें जलापूर्ति के 6, सीवरेज और एसटीपी मैनेजमेंट के 3, ड्रेनेज के 2, अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक और ग्रीन स्पेस के दो प्रोजेक्ट शामिल हैं। जलापूर्ति, सीवरेज कनेक्टिविटी और एसटीपी मैनेजमेंट के 9 प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के एवज में आईपीएच को पैसा देने का निर्णय लिया गया था लेकिन अब सरकार ने पानी और सीवरेज व्यवस्था नगर निगम के अधीन देने का फैसला ले लिया है। इसलिए पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

'ईगो प्रॉब्लम रहेगी तो नहीं हो सकता काम'

एमसी की बैठक में एसीएस-मेयर ने एक दूसरे पर जमकर कसे तंज

विश्वास भारद्वाज

शिमला। अमृत मिशन योजना में शिमला का पहला साल पूरा होने पर आयोजित बैठक के दौरान शनिवार को सरकार और नगर निगम के बीच अप्रत्यक्ष रूप से चली आ रही खींचतान खुल कर सामने आ गई। बैठक में सरकार की प्रतिनिधि के रूप में पहुंची अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) मनीषा नंदा और नगर निगम के मेयर संजय चौहान ने परोक्ष रूप से एक दूसरे पर जमकर तंज कसे। एसीएस ने मेयर को सलाह देते हुए कहा कि 'ईगो प्रॉब्लम होगी तो कोई काम नहीं होगा'। उधर मेयर ने कहा कि 'पीलिया फैलने के बाद नगर निगम की पहल से ही सरकार ने पहली बार शिमला ही नहीं पूरे प्रदेश में पानी की क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर फोकस करना शुरू किया है। नगर निगम को इसका श्रेय मिलना चाहिए।'

मनीषा नंदा ने कहा कि शहर के विकास में सरकार कभी हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार ने हमेशा निगम के हितों को ध्यान में रखा है, इसलिए निगम को भी आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन में असली काम तो अब शुरू होगा क्योंकि अब प्रोजेक्ट मूर्त रूप लेगा। पब्लिक को काम नहीं दिखा तो नगर निगम के साथ सरकार की भी बदनामी होगी। पब्लिक जन प्रतिनिधियों से तो जवाब मांगेगी ही, अधिकारियों से भी हिसाब मांगा जाएगा। एसीएस ने नगर निगम को शिमला शहर को मिली विरासत सहेजने की सीख दी और पर्यावरण की अनदेखी न करने को लेकर आगाह किया।

मेयर संजय चौहान ने कहा कि शहर के विकास के लिए सरकार और नगर निगम के बीच सही तालमेल जरूरी है, लेकिन कई मामलों में सरकार नगर निगम को परमिशन देने में छह महीने से एक साल का वक्त लगा रही है। पीलिया से नगर निगम को बड़ा सबक मिला, इससे बहुमूल्य जिंदगियों का नुकसान भी हुआ। मेयर ने कहा कि अमृत मिशन में सुझाए गए सुधारों को लेकर अगर सरकार अपना हिस्से का काम निर्धारित समय पर कर देती है तो केंद्र सरकार से नगर निगम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि हासिल करने में भी कामयाब हो जाएगा। सरकार का सहयोग मिले तो अमृत की तरह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी नगर निगम अव्वल रहेगा।

मेयर का जवाब, पीलिया पर सोई थी सरकार, एमसी ने जगाया

कहा, तालमेल जरूरी, पर सरकार लगा रही वक्त

'फर्स्ट सिटीजन' का बोलना तो जरूरी है'

एसीएस मनीषा नंदा के संबोधन के बाद कमिश्नर पंकज राय ने मेयर संजय चौहान से संबोधन के लिए आग्रह किया। मेयर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मुझे भी बोलना पड़ेगा।' इस पर मनीषा नंदा बोलीं 'फर्स्ट सिटीजन' का बोलना तो जरूरी है'।

'मैडम बंगाल की हैं, इनको माइक की जरूरत नहीं'

एसीएस मनीषा नंदा को जब संबोधन के लिए माइक आफर किया गया तो उन्होंने इंकार कर दिया। इस पर मेयर ने चुटकी लेते हुए कहा, मैडम बंगाल की हैं इन्हें माइक की जरूरत नहीं है। मनीषा नंदा ने जवाब दिया, 'मेरी आवाज भी बुलंद है और आत्म विश्वास भी पूरा है।'

आयुक्त ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिया श्रेय

निगम आयुक्त पंकज राय ने अमृत मिशन में शिमला के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के सहयोग से ही निगम को अमृत मिशन में हर संभव मदद मिल पाई है।

अमृत के तहत पूरे किए 29 करोड़ के प्रोजैक्ट

स्पैशल हाऊस : एक साल पूरा होने पर नगर निगम ने बुलाया विशेष सदन, आयुक्त ने गिनाई उपलब्धियां; बेहतर कार्य करने पर केंद्र से मिलेगी अतिरिक्त राशि

शिमला, 25 जून (वंदना): अमृत मिशन के तहत नगर निगम शिमला ने एक साल में 29 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों को अमलीजामा पहनाया है। इनमें से अधिकांश कार्य निगम द्वारा पूरे कर लिए गए हैं जबकि कुछेक कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। शनिवार को नगर निगम प्रशासन ने अमृत मिशन के एक साल पूरे होने के अवसर पर रोटरी टाऊन हॉल में विशेष सदन आयोजित किया। सदन की अध्यक्षता नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने की।

अमृत मिशन के तहत एक साल में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने के लिए मेयर संजय चौहान ने अधिकारियों समेत पार्षदों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और जनता के नुमाइंदों ने कम से कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि निगम को एक साल में मिले पैसों को खर्चने के लिए करीब 3 माह ही मिले थे, बावजूद इसके निगम ने बढ़िया काम करते हुए राशि लैप्स नहीं होने दी। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा भी खासतौर से मौजूद रहीं। उन्होंने एक साल के अंदर किए गए कार्यों के लिए निगम की सराहना करते हुए कहा कि सरकार निगम को हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है। इस दौरान सदन में डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर, पार्षद शशि शेखर, अनूप वैद्य, भारती सूद, कांता सुयाल, कला शर्मा, नरेन्द्र ठाकुर, संजय परमार, शैलेन्द्र चौहान, रजनी सिंह, सत्या कौंडल, मनोज कुठियाला व कल्याण चंद सहित अन्य पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे।

शिमला : बैठक को संबोधित करतीं अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा। (छाया)

यहां होगा इतना पैसा खर्च

अमृत के तहत नगर निगम 3 सालों में शहर में वाटर सिस्टम को मजबूत करने के लिए 41.65 करोड़ रुपए खर्च करेगा जबकि पहले चरण में पानी पर 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे जबकि सीवरेज पर निगम 37.28 करोड़ 3 सालों में खर्च करेगा। पहले चरण में निगम 13.71 करोड़ खर्च करेगा। शहर के हर छोटे-बड़े नाले व नालियों का सही चैनेलाइजेशन कर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। निगम इसके लिए 3 सालों में 0.84 लाख खर्च करेगा जबकि पहले वर्ष में इस पर 0.28 लाख खर्च करेगा। इसके तहत शहर में पार्क निर्माण पर कुल 3 सालों में 2.16 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 0.72 लाख व्यय किए जाएंगे। वहीं शहर के अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर 6.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं।

खर्च किए जाएंगे 70 करोड़

अमृत मिशन के तहत वर्ष 2016-17 के लिए 70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से शहर में सीवरेज एवं पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज व ग्रीन पार्क विकसित किए जाएंगे। अमृत मिशन के तहत पहले 3 साल में 88.23 करोड़ की राशि मिलेगी। अमृत के तहत नए प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष केंद्र से केवल 29.41 करोड़ की राशि ही विकास कार्य के लिए मिल सकेगी।

शिमला : रोटरी क्लब में अमृत योजना को लेकर आयोजित बैठक में उपस्थित पार्षद व निगम अधिकारी। (छाया)

रिफोर्म्स को मिलेंगे 2.3 करोड़ रुपए अतिरिक्त

वहीं नगर निगम द्वारा अमृत मिशन की 28 रिफोर्म्स निर्धारित किए गए थे, जिनमें से 26 पूरे कर लिए गए हैं और निगम ने इसके लिए क्लेम कर दिया है। 15 जुलाई तक केंद्र से एक टीम आएगी और आकलन करेगी कि निगम ने जो रिफोर्म पूरे करने की बात कही है, क्या वे सही हैं। अगर निगम रिफोर्म खरा उतरता है तो योजना की गाइड लाइन के तहत शिमला को करीब 2.3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिल सकेगी।

आई.पी.एच. अधिकारी होंगे नोडल ऑफिसर

वहीं अब अमृत मिशन में नगर निगम की ओर से सहायक आयुक्त प्रशांत सरकैक को नोडल ऑफिसर बनाया गया था लेकिन अब आई.पी.एच. सर्कल निगम के अधीन आने के बाद यह जिम्मेदारी एस.ई. को सौंपी जाएगी। सरकार की ओर से सर्कल की अधिसूचना मिलने के बाद निगम नोडल ऑफिसर बदलेगा।

अमृत के तहत निगम ने इन कामों पर खर्च किया पैसा

नगर निगम ने अमृत के तहत एक साल में शहर के पानी व सीवरेज पर अधिक पैसा खर्च किया है। इसमें से निगम ने तेजी से काम करते हुए जून, 2016 तक इस राशि से 14 अलग-अलग कार्य कार्यान्वित किए हैं। इन 14 में से अधिकांश कार्य अब पूरे हो गए हैं, जिसमें स्नोडन पंप हाऊस की मुरम्मत, पानी की लीकेज बंद करने पर 2.3 करोड़, 4.23 करोड़ रुपए के सीवरेज वर्कर्स सहित पानी की मेन लाइन की मुरम्मत मुख्य है। इसके अलावा अमृत के तहत 2.10 करोड़ से सब्जी मंडी में पार्किंग, 72 लाख से 8 हजार व 4 हजार क्षमता के वाटर टैंकर, 21 लाख से स्नो मशीन, कृष्णानगर में 9 लाख से नाला सुधार, टका बैंच में पार्क की इंप्रूवमैंट का काम प्रोग्रैस पर है। इस दौरान आयुक्त ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम चल रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए टाइम लाइन फिक्स करें, ताकि वे जल्द से जल्द पूरे हो सकें।

Workshop on Completion of one year of AMRUT on 25-6-2016
अमृत
AMRUT
Atal Mission for Rejuvenation
and Urban Transformation
The Object of Rotary
THE FOUR-WAY TEST

THE FOUR-WAY TEST

OTHER SPECIAL HIGHLIGHTS

1.The Project audit was concluded by the audior from the European Delegation to India Delhi.

2. Total Station Survey of the proposed DEWATS site along with the selected patch at Lower Panthaghati area of Kasumpti ward have been completed.

3.PIU worked with CDD team to analyse the condition of Public/Community toilets of Rambzar, Krishnanagar & Totu ward .

4. Consultations/Meetings are to be conducted with line departments i.e. Urban Development, PWD, IPH, Forest Department, Tourism and Department of Transport .

d Waste Composting Units at Tibetan School , Chotta Shimla And lalpani is also proposed to be set up soon.

5. PIU members accompanied the UNICEF team and visited the entire Krishnanagar ward.

6. A Bio-digester for treating the biodegradable waste of Subzi Mandi Shimla is proposed.

Municipal Corporation, Shimla

Old Judicial Complex,

Near D.C. Office,

The Mall Road,

Phone: 0177-2802771 to 0177-2802776,

Fax No: 0177-2802346,

www.shimlamc.gov.in

Email: mcs_shimla@yahoo.com, mcsml-hp@nic.in